1	2	3	4	5
2.	निराश्रय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी . .	10.50	50.50	29.50
3.	परियोजना पैकेज योजना .	17.50	55.24	152.41
4.	एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना . . .	27.00	30.00	68.50
5.	कार्यशाला सह-गृह . .	49.00	60.00	40.00
6.	हथकरघा विकास केन्द्र .	—	—	178.30
7.	अनुसंधान एंव विकास .	15.56	00.50	—
	विद्युतकरघा क्षेत्र			
1.	विद्युत करघा सेवा केन्द्र .	73.16	100 1;	144.11
2.	विद्युतकरघा कामगार बीमा योजना	—	—	24.35
3.	कम्प्यूटर सहायित डिजाइन केन्द्र	—	—	150.00

उत्तर प्रदेश में बुनकरों की दशा सुधारने के लिए किए जाने वाले उपाय

2052. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार उत्तर प्रदेश में बुनकरों की दशा में व्यापक सुधार लाने के लिए क्या कदम उठा रही है ; और

(ख) इस संबंध में यदि कोई प्रस्तावित योजना है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) भारत सरकार देश के हथकरघा बुनकरों जिसमें उत्तर प्रदेश के बुनकर भी शामिल हैं के विकास, कल्याण और उनकी स्थिति में सुधार लाने हेतु कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है । ये कार्यक्रम और योजनाएं कच्चे माल की आपूर्ति, करघों का आधुनिकीकरण, उत्पादन में वृद्धि करने, हथकरघा उत्पादकों की क्वालिटी में सुधार और अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए प्रौद्योगिकी और अन्य निवेश का प्रावधान तथा हथकरघा क्षेत्र में कुछ मदों को अनन्य रूप से उत्पादन के लिए आरक्षित करके पावरलूम क्षेत्र को चपेट से बचाने पर मुख्य ध्यान देते है ।

वर्ष 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निम्नलिखित योजनाओं के लिए राशि जारी की गई ।

	लाख रुपयों में
(1) निस्साहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी	21.64
(2) प्रोजेक्ट पैकेज योजना	119.25
(3) एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना	32.50
(4) राष्ट्रीय सूत बैंक योजना	54.00
(5) स्वास्थ्य पैकेज योजना	56.50
(6) समूह बीमा योजना	8.00
(7) कार्यशाला सह आवास	182.00
(8) प्रवर्तन मशीनरी की स्थापना	15.14
(9) विपणन विकास सहायता/रिबेट	496.51
(10) जनता कपड़ा योजना	2936.10
	3921.64

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त सरकार ने हथकरघा विकास केन्द्रों और उत्कर्ष रंगाई इकाईयों की स्थापना से हथकरघाबुनकरों को सहकारी क्षेत्र में लाने का व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है ।

Reservation of export quota by apparel exports promotion council

2053. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it has been decided to reserve quotas of garment exports regulated through the apparel Exports Promotion Council (AEPC) in the context of Government's declared policy to give economic reservations in favour of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in the matter of allotment of quotas of public agencies; and

(b) if so, the details thereof; and if not, the reasons for non-implementation of the reservation policy by the AEPC?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) Government has framed the Garment Export Entitlement Distribution Policy for distribution of garment quotas in a non-discriminatory manner with the objective, *inter alia*, of maximising our foreign exchange earnings. In the Policy, there is no reservation in favour of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the matter of allotment of quotas. The Apparel Export Promotion Council is only one of the agencies selected for the implementation of the Policy.

Import of cotton

2054. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the quantity of cotton imported during the last three years;

(b) whether Government are considering any strategy to make India's presence more stable in the international market;